

रजिस्टर्ड नं० एल०-३३/एस० एम०/१३-१४/९६.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, ७ मार्च, १९९६/ १७ फाल्गुन, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-४, ७ मार्च, १९९६

संख्या १-२८/९६-वि० सु०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, १९७३ के नियम १३५ के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश किसान पास बुक विधेयक, १९९६ (१९९६ का विधेयक

संख्यांक 13) जो दिनांक 7 मार्च, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

1996 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश किसान पास बुक विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथापुरःस्थापित रूप में)

किसानों को राजस्व संपदा में उनके अधिकार अभिलेख और कृषि धृतियों के दायित्वों से युक्त किसान पास बुक जारी करने और उन्हें उधार सुविधाएं प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने तथा उनसे सम्बन्धित या आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सैतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश किसान पास बुक अधिनियम, 1996 है।

संक्षिप्त
नाम, विस्-
तार और
प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) “कृषि” के अन्तर्गत हैं, भूमि को खेती करने के लिए उपयुक्त बनाना, भूमि का जोतना, भूमि सुधार, जिसमें सिंचाई स्त्रोतों के विकास, भूमि संरक्षण और भूमि सुधार उपाय सम्मिलित हैं फसलों की उगाई और कटाई, औद्योगिकी, वानिकी, पशु प्रजनन, पशु पालन, दुग्ध उद्योग, बीज खेती करना, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, कुक्कट पालन तथा कृषि उपज आदि के परिवहन सहित अन्य क्रियाकलाप जो कृषकों, दुग्ध उत्पादकों, पशु प्रजनकों, कुक्कट पालकों और उसी प्रकार के क्रिया-कलापों में लगे हुए अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा साधारणतया किए जाते हैं, और “कृषि प्रयोजन” शब्दों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) “वित्तीय सहायता” से वित्तीय संस्था या सरकार द्वारा, कृषि प्रयोजनों के लिए उधार, अग्रिम या अन्यथा दी गई सहायता अभिप्रेत है;

(ग) “वित्तीय संस्था” से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं,—

1949 का
10

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी;

1955 का
23

(ii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;

1959 का
38

(iii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक;

- (iv) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 1970 का 5
की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी नया बैंक;
- (v) कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित 1963 का
कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम; 10
- (vi) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कृषिक वित्त निगम सीमित; 1956 का 1
- (vii) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधीन स्थापित प्रादेशिक 1976 का
ग्रामीण बैंक; 21
- (viii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अधीन 1981 का
स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; 61
- (ix) हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 के अधीन रजिस्ट्री- 1969 का
कृत या रजिस्ट्रीकृत समझा गया कोई सहकारी बैंक और सहकारी सोसाइटी,
जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को, इस धारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित
वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है; 3
- (x) हिमाचल प्रदेश को-ऑपरेटिव ऐग्रीकलचर एण्ड रूरल डिवेलपमेंट बैंक ऐक्ट, 1979 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव ऐग्रीकलचर 1979 का
एण्ड रूरल डिवेलपमेंट बैंक तथा ऐग्रीकलचर एण्ड रूरल डिवेलपमेंट प्राइमरी 23
बैंक,
- (xi) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में
वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था;
- (घ) "किसान" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका धृति में चहे भू-स्वामी, अभिधारी,
बन्धकदार या पट्टेदार के रूप में हित है और आवासीय प्रयोजनों के लिए
आवंटित प्लाट धोरक के सिवाय, पंचायत और सरकारी भूमि का पट्टेदार
इसके अन्तर्गत है;
- (ङ) "किनान पास बुक" से ऐसी पास बुक अभिप्रेत है जो हिमाचल प्रदेश
भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा-32 (2) (क) के अधीन 1954 का
रखे गए अधिकारों के अभिलेख से अधिप्रमाणित उद्धरणों से युक्त 6
हो और जिसमें किसान के उसकी कृषि सम्बन्धी धृति या राजस्व
सम्पदा में धृतियों में हित की प्रकृति और सीमा तथा अन्य विशिष्टियां
जो विहित की जाएं, दर्शाई गई हों, पास बुक अभिप्रेत है;
- (च) "भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो नगर या गांव में किसी भवन के
स्थल के रूप में अधिभोग में नहीं है और जो कृषि प्रयोजनों के लिए
या कृषि की अनुसेवी प्रयोजनों के लिए या चरागाह के लिए अधिभोग
में है या पट्टे पर दी गई है और ऐसी भूमि पर भवनों के स्थल और अन्य
संरचना इसके अन्तर्गत हैं;
- (छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा
विहित अभिप्रेत है;
- (ज) "लोक सेवक" से भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 में 1860 का
यथा परिभाषित लोक सेवक अभिप्रेत है; 45
- (झ) "राजस्व अधिकारी" से वृत्त राजस्व अधिकारी या इस अधिनियम के
प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी
अभिप्रेत है;

(ञ) "उप-रजिस्ट्रार" का वही अर्थ होगा जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में इसका है; और

(ट) किसी अधिकार, हक या हित के धारक को द्योतित करने के लिए प्रयुक्त शब्दों और पदों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के किसी अधिकार, हक या हित के पूर्वाधिकारी और उत्तराधिकारी भी समझे जाएंगे; और उन सभी शब्दों और पदों का, जो हिमाचल प्रदेश ठेनन्स एण्ड लैंड रिकारम ऐक्ट, 1972 और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में परिभाषित हैं किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, जहां कहीं भी वे इसमें प्रयुक्त हैं, वही अर्थ लगाया जाएगा जो उन अधिनियमों में इनका है।

3. इस अधिनियम के उपबन्ध या तदधीन बनाए गए कोई नियम, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

4. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्, यथाशीघ्र, प्रत्येक पटवारी द्वारा अपनी राजस्व सम्पदा में प्रत्येक किसान को किसान पास बुक जारी की जाएगी :

परन्तु सह भागी के सम्बन्ध में, संयुक्त धृति में उनके हित और सीमा को दर्शाते हुए, प्रविष्टि की जाएगी :

परन्तु यह और कि उस राजस्व सम्पदा में, जहां बन्दोबस्त या चकबन्दी संक्रियाओं का संचालन किया जा रहा है, ऐसी संक्रियाओं की समाप्ति और अधिकारों के अभिलेख तैयार किए जाने पर, यथाशीघ्र, नई किसान पास बुक जारी की जाएगी।

5. (1) किसान पास बुक, ऐसे प्ररूप में, कितान की ऐसी विशिष्टियों से युक्त और ऐसी अवधि के लिए जो विहित की जाए विधिमान्य होगी।

(2) किसान पास बुक ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सम्पूर्ण की जाएगी।

(3) नामांतरण अनुप्रमाणन या अन्यथा धृति में किसान के हित में किन्हीं परिवर्तनों के विषय में किसान पास बुक प्रस्तुत किए जाने के समय राजस्व अधिकारी, नामांतरण कार्यवाहियों और अन्य सुसंगत साक्ष्य के आधार पर परिवर्तनों की शुद्धता के बारे में समाधान हो जाने पर, ऐसे परिवर्तनों के विषय में किसान पास बुक में, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए प्रविष्टि करेगा।

(4) किसान पास बुक का धारक किसान पास बुक के मुख्य पृष्ठ पर दर्शित तारीख के अवसान के पश्चात् इसका अद्यतन करवाने के लिए बाध्यकर होगा, अन्यथा जब भी यह प्रस्तुत की जाएगी तो विधिक दस्तावेज के रूप में ग्रहण नहीं की जाएगी। सदर कार्यालय में राजस्व सम्पदा की अगली जमाबन्दी के परेक्षण के

अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना।

किसान पास बुक का जारी किया जाना।

किसान पास बुक की विषय-वस्तु।

1908 का 16

1974 का 8

1954 का 6

1908 का 16

तुरन्त पश्चात्, किन्तु तीस अप्रैल के पश्चात् नहीं, किसान पास बुक का धारक इसको यथा विहित रसीद के विरुद्ध नई जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियों के अद्यतन के लिए पटवारी को देगा। फिर भी, किसान पास बुक के अद्यतन के लम्बित रहने पर पूर्ववर्ती जमाबन्दी की अवधि के लिए उसकी प्रविष्टियां केवल उस अवधि के लिए ही विधिमान्य रहेंगी।

प्रविष्टियों की सत्यता की उप-धारणा।

6. (1) धारा 4 के अधीन जारी किसान पास बुक में धारा 5 में विहित रीति से की गई प्रत्येक प्रविष्टि, तब तक सत्य उपधारित की जाएगी जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं की जाती है।

(2) लोक सेवकों, न्यायालयों या वित्तीय संस्थाओं के समक्ष किसान पास बुक की प्रविष्टियों का साक्ष्यक मूल्य, वही होगा मानो वे सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए अधिकारों के अभिलेख और अन्य अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां हों।

(3) यदि किसान पास बुक में कोई त्रुटि हो तो सहायक कनेक्टर, द्वितीय श्रेणी को, आवेदन करके उस पर आक्षेप किया जा सकता है, जो इसे परिशुद्ध करने के लिए ऐसे समुचित आदेश करेगा जैसे वह ठीक समझे।

किसान पास बुक पेश किए बिना अन्तरण का रजिस्ट्रीकृत न किया जाना।

7. (1) किसान पास बुक के धारक द्वारा ऐसी किसान पास बुक में विनिर्दिष्ट किसी भूमि या ऐसी भूमि में किसी हित अथवा उसमें खड़ी किसी फसल के बारे में किया गया कोई अन्तरण, तब तक उप-रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि किसान पास बुक उसके समक्ष पेश नहीं की जाती, और उसके पेश करने पर, वह उस द्वारा रजिस्ट्रीकृत अन्तरण की विविष्टियों को ऐसे प्ररूप और रीति में सम्मिलित करेगा, जो विहित की जाए।

(2) इस धारा के उल्लंघन में किया गया कोई अन्तरण शुन्य होगा।

किसान पास बुक पेश किए बिना राजस्व अभिलेख में परिवर्तन न किया जाना।

8. (1) राजस्व अधिकारी द्वारा, भूमि या उसमें किसी हित के किसी अन्तरण के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन, किसान पास बुक के पेश किए बिना नहीं किया जाएगा।

(2) राजस्व अधिकारी द्वारा, भूमि के किसी अधिकार या हित के अन्तरक या अन्तरिती को नोटिस जारी करके मांग पर, किसान पास बुक को पन्द्रह दिन के भीतर पेश करने का निदेश देना, विधिपूर्ण होगा और ऐसे अन्तरक या अन्तरिती के लिए, व्यक्तिगत तौर पर या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से किसान पास बुक को परिवर्तन दर्शित करने वाली प्रविष्टि करने के लिए पेश करना आवश्यक होगा।

(3) इस धारा के उल्लंघन में किया गया कोई परिवर्तन शुन्य होगा।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता देना।

9. (1) वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसान को किसान पास बुक पेश किए जाने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिर भी, वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए फसल-ऋणों के लिए किसान पास बुक पेश करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) किसान पास बुक के धारक को कोई वित्तीय सहायता देने वाली वित्तीय संस्था ऐसी वित्तीय सहायता के तथ्य को किसान पास बुक में सम्मिलित करेगी और

जहां वित्तीय सहायता किसी धृति की प्रतिभूति पर दी गई हो वहां वित्तीय संस्था उस धृति के विरुद्ध प्रविष्टि करेगा, जिसकी प्रतिभूति पर इस द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है, और इस प्रकार की गई प्रविष्टि, वित्तीय संस्था के पक्ष में उस धृति पर परिवर्तन सृजित करने का प्रभाव रखेगी जिसके विरुद्ध ऐसी प्रविष्टि की गई है और किसान पास बुक का धारक उस धृति का अन्यसंक्रामण करने से तब तक विवर्जित होगा जब तक कि वित्तीय संस्था द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की बकाया राशि, उस पर देय ब्याज सहित प्रतिसंदत्त न कर दी गई हो :

परन्तु जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी किसान द्वारा किसी वित्तीय संस्था के पक्ष में किसी भूमि पर कोई प्रभार या उसमें हित सृजित किया गया था, वहां यह उसे ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी वित्तीय संस्था के पक्ष में, ऐसी संस्था द्वारा उसको दी गई किसी वित्तीय सहायता की प्रतिभूति के रूप में ऐसी भूमि पर कोई पश्चात्पूर्वी प्रभार या उसमें हित सृजित करने से विवर्जित नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि किसान पास बुक जारी करने के पश्चात् प्रथम उधार देने वाली वित्तीय संस्था, 15 दिन के भीतर, यथास्थिति, वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए सभी बकाया उधारों (फसल उधार के सिवाय) और उन किसानों द्वारा सृजित विलगनों को, उस प्रभाव का शपथपत्र प्राप्त करके अभिनिश्चित और सत्यापित करेगी और उन व्यौरों की किसान पास बुक में प्रविष्टि करेगी और अधिप्रमाणित करेगी।

(3) वित्तीय संस्था किसान पास बुक में सम्मिलित सुसंगत प्रविष्टियों की एक प्रति उस राजस्व अधिकारी तथा उप-रजिस्ट्रार को भी पृष्ठांकित करेगी जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर इस प्रकार प्रभारित सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और उसकी प्राप्ति पर राजस्व अधिकारी, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन रखे गए अधिकारों के अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करवाएगा।

10. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् सरकार के पक्ष में किसी भूमि या हित अथवा उस पर खड़ी फसल पर सृजित प्रभार या बन्धक की, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसान द्वारा, वित्तीय संस्था द्वारा उसे दी गई वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय संस्था के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में ऐसी भूमि या हित पर सृजित प्रभार या बन्धक पर, पूर्विकता होगी।

प्रभार की पूर्विकता।

11. धारा 4 के अधीन जारी और अद्यतन की गई किसान पास बुक आगामी जमा-बन्दी तक प्रवृत्त रहेगी और तत्पश्चात् केवल तभी वैध होगी, यदि यह अद्यतन की गई हो और उस रीति में प्रमाणित की गई हो, जैसी विहित की जाए।

किसान पास बुक की कालिकता।

12. किसान को किसान पास बुक, ऐसी रकम के संदाय पर जारी की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

किसान पास बुक का दाम।

13. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां, सरकार या किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के विरुद्ध न होंगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

राजस्व अधिकारी के आदेशों की अवज्ञा करने और किसान पास बुक में प्रक्षेप आदि करने के लिए शास्ति ।

14. (1) यदि कोई व्यक्ति राजस्व अधिकारी द्वारा मांगने पर किसान पास बुक को पेश करने में असफल रहता है या इन्कार करता है अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी को कपट-वंचित करने के आशय से किसान पास बुक में प्रक्षेप करता है या कोई चीज भिटाता है अथवा संदोषतः अभिलाष प्राप्त करने की दृष्टि से जानबूझ कर या विश्वास रखते हुए कि वह मिथ्या है अथवा जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, कोई मिथ्या कथन करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) कोई भी न्यायालय उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, राजस्व अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के सिवाए, संज्ञान नहीं करेगा । तथापि, वित्तीय संस्थाएँ किसान पास बुक में उनके ध्यान में आई किसी हेरा-फेरी के बारे में राजस्व अधिकारी को सूचित कर सकेंगी । हेरा-फेरी से बचने के लिए किसान पास बुक के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा और प्रत्येक पृष्ठ पर किसान का नाम लिखा जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

15. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपग्रन्थों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्ट तथा और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे —

- (क) धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन किसान पास बुक का प्ररूप, विशिष्टियाँ और विधिमान्यता की अवधि ;
- (ख) धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन किसान पास बुक को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति और रीति ;
- (ग) प्ररूप और रीति जिसमें धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन किसान पास बुक में प्रविष्टि की जाएगी ;
- (घ) प्ररूप और रीति जिसमें धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अन्तरण की विशिष्टियाँ किसान पास बुक में सम्मिलित की जाएँगी ;
- (ङ) वह रीति जिसमें धारा 11 के अधीन किसान पास बुक अद्यतन और प्रमाणित की जाएगी ;
- (च) धारा 12 के अधीन किसान पास बुक का दाम ; और
- (छ) कोई अन्य विषय जिसके लिए राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक है ।

(3) इस धारा या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जान के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के जिसमें इसे रखा गया है के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवधान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

- 1954 का 6 16. हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 168 के अधीन बनाए गए और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त हिमाचल प्रदेश किसान पास बुक नियम, 1982 उस तारीख के पश्चात् भी प्रवृत्त रहेंगे जब तक वे संशोधित, परिवर्तित या विखण्डित नहीं किए जाते, मानो ऐसे नियम इस अधिनियम के अधीन बनाए गए थे और उन नियमों के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत जारी की गई किमान पास बुकें भी हैं) वैसे ही विधिमन्य और प्रवर्तनशील होंगी मानो यह इस अधिनियम के अनुबन्धों के अनुसार ही है।
- नियमों का चालू रहना और तद्धीन की गई कार्रवाई का विधिमन्य-करण।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः किसान अपनी भूमि के बारे में अभिलेखों से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए पूर्णतः पटवारी पर निर्भर है। वह भूमि पर अपने अधिकारों के बारे में निश्चित नहीं है और उसे उधार अभिप्राप्त करने तथा छोटे-छोटे मामलों में अपनी भूमि के राजस्व अभिलेख प्राप्त करने के लिए पटवारी के पास जाना पड़ता है। इससे उसे अत्यधिक अशुविधा होती है और इससे उन अनैतिक व्यक्तियों के कारण अनाचार को बढ़ावा मिलता है जो उनकी अज्ञानता का लाभ उठाते हैं। बहुत से मामलों में इससे सिविल मुकद्दमेबाजी बढ़ी है और परिणामस्वरूप किसान को अनावश्यक व्यय करना पड़ा है।

इमलिए--

- (i) अपनी भूमि के अभिलेख की प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए किसानों की पटवारी पर निर्भरता दूर करने ;
- (ii) अपनी धृति के वास्तविक कब्जे की जानकारी के लिए किसान को समर्थ बनाने;
- (iii) अपनी भूमि से सम्बन्धित विधिक/वित्तीय विषयों में किसान को और अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराने ;
- (iv) किसानों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से उधार प्राप्त करने को सुकर बनाने; और
- (v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी भूमि का अभिलेख अद्यतन और उनमें अभिलिखित तथ्य साक्ष्य के रूप में ग्राह्य रहें ;

किसान पास बुक की तैयारी और जारी किए जाने को विनियमित करने के लिए, विधि का अधिनियमित किया जाना आवश्यक हो गया है।

ठाकुर गुलाब सिंह,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

7 मार्च, 1996.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के उपबन्धों को विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किया जाएगा। विधेयक का खण्ड 12 यह उपबन्ध करता है कि किसान पास बुकें राज्य सरकार द्वारा नियत दाम के संदाय पर जारी की जाएंगी। तथापि, किसान पास बुकें तैयार करने और जारी करने के लिए राजकोष से कुछ अतिरिक्त व्यय अन्तर्बलित होगा जिसका स समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 15, उसमें विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए मशवत करता है और इस प्रकार बनाए गए नियम विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे। प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य प्रकृति का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
[राजस्व विभाग नस्ति सं० रैव-2 एफ(1) 3/82-V]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश किसान पास बुक विधेयक, 1996 की विषय-वस्तु :
बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक व विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 13 of 1996.

THE HIMACHAL PRADESH KISAN PASS BOOK BILL, 1996

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the issue of Kisan Pass Books to Kisans containing record-of-rights and liabilities of their agricultural holdings in a revenue estate and to enable them to have credit facilities and for other matters connected or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Kisan Pass Book Act, 1996.

Short title,
extent and
commence-
ment.

5 (2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) “agriculture” includes making land fit for cultivation, cultivation of land, improvement of land including development of sources of irrigation, soil conservation and land development measures, raising and harvesting of crops, horticulture, forestry, cattle breeding, animal husbandry, dairy farming, seed farming, pisciculture, sericulture, bee-keeping, piggery, poultry farming and other activities including transportation of agricultural produce etc., as are generally carried on by agriculturists, dairy-farmers, cattle breeders, poultry farmers and other categories of persons engaged in similar activities and the words ‘agricultural purposes’ shall be construed accordingly ;

(b) “financial assistance” means an assistance rendered by way of loans, advances or otherwise for the purposes of agriculture by a financial institution or Government ;

(c) “financial institution” means and includes,—

(i) a banking company as defined in clause (e) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949;

(ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955;

(iii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

(iv) a corresponding new bank as specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;

10 of 1949

23 of 1955

33 of 1959

5 of 1970

- (v) the Agriculture Refinance and Development Corporation established under the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963; 10 of 1963
- (vi) the Agricultural Finance Corporation Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956; 1 of 1956
- (vii) the Regional Rural Bank established under the Regional Rural Banks Act, 1976; 21 of 1976
- (viii) the National Bank for Agriculture and Rural Development established under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981; 61 of 1981
- (ix) the Co-operative Bank and a Co-operative Society registered or deemed to be registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 the object of which is to provide financial assistance as defined in clause (b) of this section to its members; 3 of 1969
- (x) the Himachal Pradesh State Co-operative Agricultural and Rural Development Bank, and the Primary Agricultural and Rural Development Bank established under the Himachal Pradesh Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Act, 1979; 23 of 1979
- (xi) any other financial institution notified by the State Government in the Official Gazette, as a financial institution for the purposes of this Act;
- (d) "Kisan" means a person having an interest in a holding whether as a land owner, tenant, mortgagee, pattadar, including lessee of Panchayat and Government land, except holder of a plot allotted for residential purposes;
- (e) "Kisan Pass Book" means a Pass Book containing certified extracts from record-of-rights maintained under section 32 (2) (a) of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 showing the nature and extent of interest of a Kisan in his agricultural holding or holdings in a revenue estate and other particulars as may be prescribed; 6 of 1954
- (f) "land" means land which is not occupied as the site of any building in a town or village and is occupied or has been let for agricultural purposes or for purposes subservient to agriculture, or for pasture, and includes the sites of buildings and other structure on such land;
- (g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (h) "public servant" means the public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code, 1860; 45 of 1860
- (i) "Revenue Officer" means the circle Revenue Officer or any other officer appointed by the State Government for the purposes of this Act;
- (j) "Sub-Registrar" shall have the same meaning as is assigned to it in the Registration Act, 1908; and 16 of 1908
- (k) the word and expressions used to denote the holder of any right, title or interest shall be deemed to include the predecessors and successors of any right, title or interest of such person; and all the words and expressions defined in the Himachal Pradesh

8 of 1974
6 of 1954

Tenancy and Land Reforms Act, 1972 and Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, but not defined in this Act, shall wherever used herein be construed to have the meanings assigned to them by the said Acts.

16 of 1908

3. The provisions of this Act or any rule made thereunder shall have effect notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908, or in any other law for the time being in force.

Act to override other laws.

4. As soon as may be after the commencement of this Act, there shall be issued by each Patwari, a Kisan Pass Book to every Kisan in his revenue estate :

Issue of Kisan Pass Book.

Provided that in respect of co-shares an entry shall be made showing the extent and nature of their interest in the joint holding :

Provided further that in the revenue estate where settlement or consolidation operations are being conducted, a fresh Kisan Pass Book shall be issued as soon as operations are concluded and record-of-rights is prepared.

5. (1) The Kisan Pass Book shall be in such form containing such particulars of the Kisan and valid for such period as may be prescribed.

Contents of Kisan Pass Book.

(2) The Kisan Pass Book shall be completed by such persons and in such manner as may be prescribed.

(3) On the presentation of the Kisan Pass Book at the time of attestation of mutation or otherwise with regard to any changes in the interest of the holding of the Kisan, the Revenue Officer, after being satisfied of the correctness of the changes on the basis of the mutation, proceedings and other relevant evidence, shall make an entry with respect to such changes in the Kisan Pass Book in such form and manner as may be prescribed.

(4) It will be obligatory on the part of the Kisan Pass Book holder to get it updated after the expiry date mentioned on title page of the Kisan Pass Book, otherwise it will not be entertained as legal document whenever presented. Soon after the consignment of the next jamabandi of the revenue estate in the Sadar Office but not later than 30th April, the holder of the Kisan Pass Book shall hand it over to the Patwari for updating the entries according to the new jamabandi against receipt as may be prescribed. However, pending updation of the Kisan Pass Book, the entries therein for the period of the preceding jamabandi would continue to remain valid for that period only.

6. (1) Every entry made, in the manner prescribed in section 5, in the Kisan Pass Book issued under section 4 shall be presumed to be true until the contrary is proved.

Presumption of truth as to entries.

(2) The entries in the Kisan Pass Book shall carry the same evidentiary value as if these were certified copies of the record-of-rights and other public record, for all intents and purposes, before the public servant or courts or financial institutions.

(3) If there is any mistake in the Kisan Pass Book, the same can be challenged by making an application to the Assistant Collector Grade-II who shall make such appropriate orders to rectify it as he deems fit.

Transfer
not to be
registered
except on
production
of Kisan
Pass Book.

7. (1) No transfer made by the holder of a Kisan Pass Book in respect of any land specified in such Kisan Pass Book or any interest in such land or any crop standing thereon shall be registered by the Sub-Registrar unless the Kisan Pass Book is produced before him, and on the production thereof, he shall incorporate the particulars of the transfer registered by him in such form and manner as may be prescribed.

(2) Any transfer effected in contravention of this section shall be void.

Alteration
not to be
made in the
revenue re-
cord except
on produc-
tion of
Kisan Pass
Book.

8. (1) No alteration in the revenue record shall be made by the Revenue Officer as a consequence of any transfer of land or any interest therein except on the production of the Kisan Pass Book.

(2) It shall be lawful for the Revenue Officer to direct the transferor or transferee of any right or interest in the land to produce the Kisan Pass Book on demand within fifteen days by issuing him a notice and it shall be incumbent upon such transferor or transferee to produce the Kisan Pass Book either personally or through an authorised agent for making an entry indicating the change.

(3) Any alteration made in contravention of this section shall be void.

Grant of
financial
assistance
by financial
institutions.

9. (1) Financial assistance will be granted by a financial institution to a Kisan on production of Kisan Pass Book. However, production of Kisan Pass Book will not be necessary for crop loans advanced by financial institutions.

(2) A financial institution granting any financial assistance to the holder of the Kisan Pass Book shall incorporate in the Kisan Pass Book the factum of such financial assistance and where such financial assistance has been given on the security of any holding, the financial institution shall also make an entry against the holding, on the security of which the financial assistance has been granted by it, and the entry so made shall have the effect of creating a charge in favour of the financial institution on the holding against which the entry has been made and the holder of the Kisan Pass Book shall be debarred from alienating the said holding until the outstanding amount of the financial assistance granted by the financial institution has been repaid together with interest due thereon:

Provided that where any charge on any land or interest therein was created by a Kisan in favour of a financial institution before the commencement of this Act, it shall not debar him from creating, after such commencement, a subsequent charge on such land or interest therein in favour of a financial institution as security for any financial assistance given to him by such institution:

Provided further that the financial institution which sanctions the first loan after the issue of the Kisan Pass Book shall ascertain and verify within fifteen days all outstanding loans (except crop loan) advanced by financial institutions and encumbrances created by the Kisan, as the case may be, by procuring an affidavit to that effect and shall enter and authenticate the details thereof in the Kisan Pass Book.

(3) The financial institution shall endorse a copy of the relevant entries incorporated in the Kisan Pass Book to the Revenue Officer as well as the Sub-Registrar within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property which has been so charged is situated and on receipt of the same the Revenue Officer shall cause necessary entry to be made in the record-of-rights maintained under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

10. A charge or mortgage created on any land or interest or crops standing thereon after the commencement of this Act, in favour of Government shall have priority over a charge or mortgage on such land or interest created by a Kisan in favour of a financial institution as security for financial assistance given to him by the financial institution after the commencement of this Act.

Priority of charge.

11. A Kisan Pass Book issued under section 4 and made upto date shall remain in force until the next jamabandi and shall be valid thereafter only if it has been made up-to-date and so certified in the manner as may be prescribed.

Periodicity of Kisan Pass Book.

12. The Kisan Pass Book shall be issued to a Kisan on payment of such amount as may be prescribed.

Cost of Kisan Pass Book.

13. No suit or other legal proceedings shall lie against the Government or any officer or authority for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

14. (1) If any person fails or refuses to produce a Kisan Pass Book demanded by a Revenue Officer or interpolate or erase anything in the Kisan Pass Book with an intent to defraud any authority under this Act or makes any false statement knowingly or having reasons to believe the same to be false or which he does not believe to be true with a view to gain wrongfully, shall be liable to be punished with an imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

Penalty for disobedience of orders of Revenue Officer and for interpolation etc. in the Kisan Pass Book.

(2) No court shall take cognizance of an offence punishable under sub-section (1) except on a complaint made by the Revenue Officer. However, financial institutions may inform the Revenue Officer about any tampering with in the Kisan Pass Book coming to their notice. Each page of the Kisan Pass Book will be serially numbered and name of the Kisan written on each page to avoid tampering with.

15. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette and subject to the condition of previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act.

Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

- (a) the form, particulars and period of validity of the Kisan Pass Book under sub-section (2) of section 5 ;
- (b) persons and the manner for the completion of the Kisan Pass Book under sub-section (2) of section 5 ;

- (c) the form and manner in which the entry shall be made in the Kisan Pass Book under sub-section (3) of section 5;
- (d) the form and manner in which the particulars of the transfer shall be incorporated in the Kisan Pass Book under sub-section (1) of section 7;
- (e) the manner in which the Kisan Pass Book shall be made upto date and certified under section 11;
- (f) the cost of Kisan Pass Book under section 12 ; and
- (g) any other matter for which provision is in the opinion of the Government necessary for giving effect to the purposes of this Act.

(3) Every rule made under this section or any other provision of this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the State Legislative Assembly while it is in session for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Assembly agrees in making any modification in the rule or the Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Continuation
of rules and
validation of
action taken
thereunder.

16. The Himachal Pradesh Kisan Pass Book Rules, 1982 framed under section 168 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, and in force immediately before the commencement of this Act, shall continue to be in force after that date until amended, varied or rescinded, as if such rules were made under this Act, and any action taken (including Kisan Pass Books issued) in pursuance of those rules shall be as valid and operative as if it has been taken in accordance with the provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently a farmer is entirely dependent on the Patwari for all matters connected with the records regarding his land. He is not certain about his rights over the land and wherever he has to obtain a loan or even for minor matter, has to go to the Patwari to get copies of the revenue records of the land he owns. This causes him a lot of inconvenience and also leads to malpractices because of unscrupulous persons who take advantage of his ignorance. In many cases it has led to civil litigation and consequent unnecessary expenditure by the farmer.

Thus it has become necessary to enact a law to regulate the preparation and issue of Kisan Pass Books to—

- (i) remove the dependence of the farmer on the patwaris for obtaining copies of the record of his land;
- (ii) enable the farmer to know the actual possession of his holdings;
- (iii) provide greater security to the farmer in legal/financial matters relating to his land;
- (iv) facilitate the farmers to get loans from the financial institutions;
- (v) ensure that the record of his land remains upto-date, and is admissible as an evidence of the facts recorded therein.

THAKUR GULAB SINGH,
Minister-in-charge.

SHIMLA :
The 7th March, 1996.

- (c) the form and manner in which the entry shall be made in the Kisan Pass Book under sub-section (3) of section 5;
- (d) the form and manner in which the particulars of the transfer shall be incorporated in the Kisan Pass Book under sub-section (1) of section 7;
- (e) the manner in which the Kisan Pass Book shall be made upto date and certified under section 11;
- (f) the cost of Kisan Pass Book under section 12 ; and
- (g) any other matter for which provision is in the opinion of the Government necessary for giving effect to the purposes of this Act.

(3) Every rule made under this section or any other provision of this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the State Legislative Assembly while it is in session for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Assembly agrees in making any modification in the rule or the Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Continuation
of rules and
validation of
action taken
thereunder.

16. The Himachal Pradesh Kisan Pass Book Rules, 1982 framed under section 168 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, and in force immediately before the commencement of this Act, shall continue to be in force after that date until amended, varied or rescinded, as if such rules were made under this Act, and any action taken (including Kisan Pass Books issued) in pursuance of those rules shall be as valid and operative as if it has been taken in accordance with the provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently a farmer is entirely dependent on the Patwari for all matters connected with the records regarding his land. He is not certain about his rights over the land and wherever he has to obtain a loan or even for minor matter, has to go to the Patwari to get copies of the revenue records of the land he owns. This causes him a lot of inconvenience and also leads to malpractices because of unscrupulous persons who take advantage of his ignorance. In many cases it has led to civil litigation and consequent unnecessary expenditure by the farmer.

Thus it has become necessary to enact a law to regulate the preparation and issue of Kisan Pass Books to—

- (i) remove the dependence of the farmer on the patwaris for obtaining copies of the record of his land;
- (ii) enable the farmer to know the actual possession of his holdings;
- (iii) provide greater security to the farmer in legal/financial matters relating to his land;
- (iv) facilitate the farmers to get loans from the financial institutions;
- (v) ensure that the record of his land remains upto-date, and is admissible as an evidence of the facts recorded therein.

THAKUR GULAB SINGH,
Minister-in-charge.

SHIMLA :

The 7th March, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the proposed Bill are to be enforced through the existing Government machinery. Clause 12 of the Bill provides that the Pass Books will be issued on payment of its cost to be fixed by the State Government. However, preparation and issue of Kisan Pass Books, will involve some extra-expenditure, which can not be quantified at this stage, out of the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 15 of the Bill empowers the State Government to frame the rules in respect of the matters specified therein and the rules so made are to be laid before the Legislative Assembly. The proposed delegation is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION

[Rev. Deptt. file No. Rev. 2-F (1) 3/82-V]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Kisan Pass Book Bill, 1996, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of this Bill in the Assembly.